एकता परिषद राहत अभियान

7 – 13 मई 2020 संस्करण क्रमांक – 10

एकता परिषद संगठन और जिला प्रशासन मुरैना का संयुक्त कोरोना राहत कार्य शुरु

जिला कलेक्टर, मुरैना ने गरीबों के प्रति चिंता जाहिर करते हुए संयुक्त राहत कार्य पर सहमति दी और पूरे 10000 परिवारों को इस अभियान के तहत राहत पहुॅचाने को कहा। – प्रफुल्ल श्रीवास्तव, मुरैना

जिला मुरैना – जमीनी स्तर पर काम करने वाले संस्था / संगठनों के अनुभवों तथा सीमित संसाधनों के साथ अगर जिला प्रशासन के संसाधनों ककको मिला दिया जाय तो लॉकडाउन की इस विषम परिस्थितियों में जरूरतमंद और बेसहारा वंचित वर्ग को अधिक व्यवस्थित तरीके से राहत पहुंचाई जा सकती है। ज्ञात हो कि एकता परिषद मुरैना जिला प्रशासन के साथ मिलकर "संयुक्त राहत कार्य" संचालित कर रहा है। कोरोना राहत कार्य को संचालित कर रहे एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रनसिंह परमार ने "मुरैना मॉडल" को पूरे देश मे लागू करने की जरूरत बताई। उन्होने कहा कि प्रशासन, संस्था और संगठनों को मिलकर कोरोना की इस आपदा की घड़ी मे संयुक्त प्रयास करना चाहिये जिससे जरुरतमंदो को आवश्यक राहत पहुंचायी जा सके।

कृषि मजदूरी पर निर्भर रहने वाले परिवार कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण मजदूरी नहीं कर सके है। जिससे उनके पास भोजन हालांकि सरकार के द्वारा पीडीएस के अंतर्गत जरूर राशन बांटा गया, किंतु राशन के साथ भोजन पकाने के लिए अन्य चीजें भी आवश्यक होती हैं जैसे तेल, दाल, सब्जी, नमक, मसाला इत्यादि जिसे शासन उपलब्ध नहीं कराता है। रनसिंह परमार जी ने कहा कि एकता परिषद के द्वारा जिला कलेक्टर, मुरैना से मिलकर पहाड़गढ़ के आदिवासी और दलित परिवारों की समस्याओं को साझा किया गया तथा खाद्य सामग्री के वितरण की आवश्यक्ता पर बल देते हुए अपने सीमित संसाधनों की उपलब्धता को भी कलेक्टर के समक्ष रखा गया।

जिला कलेक्टर, मुरैना ने गरीबों के प्रति चिंता जाहिर करते हुए संयुक्त राहत कार्य पर सहमति दी और पूरे 10000 परिवारों को इस अभियान के तहत राहत पहुँचाने को कहा इस निर्णय के तहत जिला कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास और एकता परिषद तथा महात्मा गांधी सेवा आश्रम के कार्यकर्ताओं के द्वारा धोबनी गॉव में 153 तथा कन्हार में 257 सहरिया आदिवासी तथा दलित परिवारों के बीच खाद्यान्न सामग्री का वितरण सामाजिक दूरी का पालन करते हुए किया गया।

वितरित की गयी सामग्री का विवरण – प्रत्येक परिवारों को जिला प्रशासन के द्वारा आटा–5 किलो, चावल–1 किलो, साबुन–1 पीस तथा एकता परिषद व महात्मा गांधी सेवा आश्रम के द्वारा दाल–1 किलो, सरसो का तेल–1 लीटर, नमक–1पैकेट, मिर्च और मसाला दिया गया। इसके अलावा 800 मास्क भी सभी परिवारों में बांटे गये।

ग्रामीणों की मांग – रोजगार गांरटी कानून के अंतर्गत गांव में रोजगार सृजन, पेयजल के लिए मोटर की व्यवस्था और खराब पड़े बिजली के ट्रांसफार्मर को बदलवाने के लिये जिला कलेक्टर ने जरूरी दिशा निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिये। जिला कलेक्टर ने पंचायत स्तर पर विकास कार्यो के लिए जरूरी प्रस्ताव अविलम्ब जिला प्रशासन को भेजने का भी निर्देश दिया ।

धोबनी में 153 और कन्हार में 257 सहरिया आदिवासी परिवारों को बांटा गया राशन

एकता परिषद और प्रशासन का संयुक्त कोरोना राहत कार्य शुरू

भास्कर संवाददाता | जौरा

एकता परिषद और जिला प्रशासन के द्वारा सहरिया परिवारों में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोरोना राहत कार्य को संचालित कर रहे रन सिंह परमार ने मुरैना मॉडल को पूरे देश में लागू करने की जरूरत बताई।

उन्होंने पहाड़गढ़ के आदिवासी और दलित परिवारों की समस्याओं को साझा किया तथा खाद्य सामग्री के वितरण की आवश्यकता पर बल देते हुए अपने सीमित संसाधनों की उपलब्धता को भी रखा। कलेक्टर ने गरीबों के प्रति चिंता जाहिर करते हुए संयुक्त राहत कार्य पर सहमति दी और पूरे 10000 परिवारों को इस अभियान के तहत राहत पहुंचाने को कहा। जिसके अनुसरण में बुधवार को कलेक्टर प्रियंका दास और एकता परिषद तथा महात्मा गांधी सेवा आश्रम के कार्यकर्ताओं के द्वारा धोबनी में 153 तथा कन्हार में 257 सहरिया आदिवासी तथा दलित परिवारों के बीच खाद्यान्न सामग्री का वितरण सामाजिक दूरी का पालन करते हुए किया गया। इस दौरान ग्रामीणों की मांग रोजगार गांरटी कानून के अंतर्गत गांव में रोजगार सृजन, पेयजल के लिए मोटर की व्यवस्था और खराब पड़े बिजली के ट्रांसफार्मर को बदलवाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान एसडीएम नीरज शर्मा, एकता परिषद से उदयभान सिंह परिहार, महात्मा गांधी सेवा आश्रम के प्रबंधक प्रफुल्ल श्रीवास्तव और कुलदीप तिवारी, संजय जादौन, कृष्णा, नरेश, हरिओम, डोंगर सहित पहाडग़ढ़ ब्लाक के अधिकारी उपस्थित थे।

राहत सामग्री बांटने कलेक्टर भी पहुंची।

संस्था और प्रशासन के द्वारा संयुक्त राहत कार्य में जिला प्रशासन की ओर से श्रीनीरज शर्मा, एस.डी.एम.,जौरा व पहाड़गढ़ ब्लॉक के सभी शासकीय अधिकारी तथा संस्था / संगठन की ओर से एकता परिषद से उदयभान सिंह परिहार, महात्मा गांधी सेवा आश्रम के प्रबंधक प्रफुल्ल श्रीवास्तव, कुलदीप तिवारी, संजय जादौन, कृष्णा, नरेश, हरिओम, डोंगर शर्मा उपस्थित रहे।

प्रवासी मजदूरों का मददगार बना एकता परिषद

स्रोत – डाउन टू अर्थ

एकता परिषद 20 राज्यों के लगभग 45 हजार मजदूरों की सूची तैयार कर उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रहा है

भोपाल – दिल्ली के वजीराबाद पुल से गाजियाबाद की ओर जाने वाली बाईपास रोड पर तीन परिवार एक–दूसरे के पीछे एक चल रहे हैं। इनमें से एक शख्स अपने फोन पर जोर–जोर से कह रहा है कि हम दिल्ली पहुंच गए हैं। बस आज रात कहीं आराम करेंगे और कल सुबह फिर चल पड़ेंगे। वह आगे कहता है कि अभी तो मैं नहीं बता सकता है कि कब तक पहुंचूंगा लेकिन पहुंच जरूर जाऊंगा। ये हैं रामवीर और जो पिछले 19 दिन से पैदल चलकर मथुरा से दिल्ली पहुंचे हैं। उन्हें कानपुर देहात जाना है। अब भी सैकड़ों किलोमीटर का सफर बचा हुआ है। पूछने पर कि आप किससे बतिया रहे हैं, वह कहते हैं, भला हो उस संगठन का जिसने हमारे फोन में 100 रुपए का बैलेंस डलवा दिया, नहीं तो घर वालों को बता ही नहीं पाते कि हम मर गए या जिंदा हैं। पूछने पर कि उस संगठन ने क्या केवल बैलेंस ही डलवाया और किसी प्रकार की मदद नहीं की? इस पर रामवीर ने कहा सूखा राशन भी 15 दिन का दिया था लेकिन अब खत्म हो गया है। यह एक रामवीर की बात भर नहीं है। इस प्रकार के प्रवासी मजदूर अपने–अपने घरों की ओर डग भरते जा रहे हैं।

देश के 20 राज्यों में भूमिहीनों के बीच काम करने वाले एकता परिषद ने विभिन्न राज्यों में फंसे लगभग 45 हजार मजदूरों की सूची बनाई है। परिषद के राष्ट्रीय समन्वयक रमेश शर्मा ने डाउन टू अर्थ को बताया कि हम तीन स्तरों पर श्रमिकों की मदद कर रहे हैं। पहला हमने अपने संगठन के माध्यम से देशभर के उन इलाकों में जहां मजदूरों की हालात अत्यंत दयनीय है, वहां पंद्रह दिन का सूखा राशन दे रहे हैं। दूसरा हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने में भी मदद कर रहे हैं। अब तक हमने मध्य प्रदेश सरकार को इस संबंध अपनी सूची दी है। और कई

राज्यों सरकारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तीसरे स्तर पर हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन श्रमिकों के फोन में 100 रुपए से लेकर 200 रुपए का बैलेंस भी डलवा रहे हैं ताकि वे अपने घर परिवार को अपनी कुशलक्षेम बता सकें।

एकता परिषद मुख्य रूप से भूमिहीनों के बीच काम करता है। **एकता परिषद के संस्थापक पीवी राजगोपाल ने डाउन टू अर्थ को** अर्मेनिया से (लॉकडाउन के कारण पिछले डेढ़ माह से वहां से फंसे हुए हैं) बताया कि अगर हम विस्थापित होने वाले मजदूरों का बड़ा वर्ग देखें तो ये वही हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। जो भूमिहीन होने के कारण आजीविका और रोजगार की तलाश में दूसरी जगह विस्थापित हो जाते हैं। वह बताते हैं, कोविड–19 महामारी के बाद लoकडाउन की स्थिति आई तो हमें उन मजदूरों का खयाल आया जो दूसरे सूबों में या अपने सूबे के किसी और जगह पर काम करते हैं। उनके पास किसी तरह का साधन नहीं है। वे अपने घर लौटना चाह रहे हैं लेकिन लौट नहीं पा रहे हैं। हमें लगा कि तत्काल इनकी मदद करनी चाहिए। हमारी कोशिश है कि जिनके पास राशन नहीं है, उन्हें राशन दें और जो किसी भी तरह लौट के आना चाह रहे हैं, उनके लिए इंतजाम करें।

संगठन के समन्वयक ने बताया कि लॉकडाउन का एलान होते ही पहले हमने सूची बनाई कि कौन–कौन लोग हैं जो लौटकर आ गए हैं। दो दिन के अंदर हमने ऐसे 14 से 15 हजार लोगों

की निशानदेही की जो मजदूर वर्ग में आते हैं। कुल 20 राज्यों में एकता परिषद काम करता है। वह बताते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मणिपुर, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में हमने तेजी से सूची पर काम किया है। यह काम अभी जारी है।

परिषद की पहली कोशिश थी कि इस बात की सटीक सूचना हासिल की जाए कि कहां से मजदूर निकले हैं और कहां फंसे हैं। मोबाइल के जरिए गूगल सर्वे शुरू कर उनके बारे में तत्काल जानकारियां इकट्ठी करनी शुरू की गई। परिषद ने अब तक ऐसे 45 हजार लोगों की सूचना एकत्रित की है जो भारत के करीब 20 राज्यों में फैले हुए हैं। अब तक संगठन ने लगभग 13 हजार परिवारों तक मदद पहुंचाई।

संगठन के अनुसार जो श्रमिक फंसे हुए हैं, उन्हें तीन तरह की श्रेणी में विभाजित किया। पहला तो जहां फंसे हैं, वहां के नोडल अधिकारी से संपर्क कर उन तक मदद पहुंचाई जाए। ऐसे कुछ मामलों में सफलता भी मिली। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में जहां एकता परिषद काम नहीं करती है, इन राज्यों में काम करने वाले जनसंगठनों से संपर्क कर मदद पहुंचाई गई। इसके अलावा संगठन ने तीसरा तरीका निकाला कि जो लोग संपर्क में हैं, सीधे उनके खाते में पैसा भेज दें जिससे वे दुकान से सामान ले सकें। मुख्य तौर पर इन तरीकों को अपना कर संगठन 13 हजार श्रमिक परिवारों तक पहुंचा है।

संगठन का कहना है कि लगभग 30 प्रतिशत श्रमिक ही वापस आ पाए हैं, 60 फीसदी से ज्यादा लोग अब भी फंसे हैं। संगठन ने अपनी सूची राज्य सरकारों के साथ साझा करनी शुरू की है। मध्य प्रदेश के श्योपुर, उत्तर प्रदेश के झांसी के 255 परिवार राजस्थान के फलौदी में फंसे हुए थे। दोनों राज्य सरकारों को इनके बारे में जानकारी साक्षा की तो सकारात्मक नतीजा निकला कि इनमें से ज्यादातर लोग वापस आ गए हैं। अब संगठन ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकारों के साथ अपनी सूची साझा कर रहा है। संगठन ने लंबी अवधि के लिए भी योजना बनाई है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर घर लौटे मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दिलवाने की कोशिश शुरू की है। संगठन का कहना है कि अभी तक छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में यह शुरू भी हो चुका है।

अंत में परिषद के राष्ट्रीय समन्वयक रमेश शर्मा कहते हैं कि देश में तीन ऐसे कानून हैं जो ढंग से लागू होते तो ऐसी विकट स्थिति ही नहीं पैदा होती। पहला, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कसमैन एक्ट, यह अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों का अधिनियम है। दूसरा अधिनियम है न्यूनतम मजदूरी कानून और तीसरा है बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास का कानून। इन तीनों कानूनों का खुला उल्लंघन हो रहा है। न उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिलती है, न उन्हें प्रवासी कानून के दायरे में कोई सुविधा दी जाती हैं। ईंट-भट्ठे जैसी जगहों पर जहां बंधुआ मजदूरी होती है, वहां हालत काफी खराब हैं। इन तीनों कानूनों के लिए जो शासकीय प्रावधान हैं और जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं वो नाकाम साबित हो रही हैं।

एकता परिषद राहत अभियान

1. मध्यप्रदेश

कोरोना काल में राहत सामग्री वितरण –

स्त्रोत – डोंगर शर्मा,ग्वालियर

जिला ग्वालियर – कोरोना संकट शुरु होते ही 22 मार्च को केन्द्रीय सरकार द्वारा एक दिवसीय जनता कर्फ्यू लगा दिया गया और उसके तुरत बाद देशव्यापी लॉकडाउन की घोषण कर दी गई। लॉकडाउन की घोषण होते ही संगठन द्वारा पलायन पर गये हुये मजदूरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काम आरम्भ कर दिया गया और सरकार पर मजदूरों को घर वापस लाने के लिये दबाव बनाया जाने लगा। इस बीच देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को विभिन्न माध्यमों से सहयोग देने का काम भी किया जाता रहा। 25 अप्रेल के बाद से मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा मजदूरों को घर वापस लाने की प्रक्रिया शुरु की गई। इस प्रक्रिया में ग्वालियर जिले में भी प्रवासी मजदूर वापस आये। इन मजदूरों के अलावा गांव में ही रह गये उन तमाम गरीब, वंचित, बेराजगार लोगों को राहत दिलाने के लिये एकता परिषद, ग्वालियर के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयास शुरु किया गया। गांव–गांव जा का ऐसे लोगों की सूची बनाई गई जो मनरेगा के तहत काम करना चाहते हैं और एक आवेदन के साथ यह सूची संबंधित अधिकारियों को दिया गया। इसके अलावा यह भी प्रयास किया गया कि सरकार के द्वारा जिन राहत सामग्री अथवा राशि के बारे में घोषणा की गई है उसे भी पात्र परिवार तक पहुॅचाने में मदद किया जाये। इसके लिये जिले के सभी कार्यकर्ता गांव–गांव जाकर राशन बंटवाने में मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं सहरिया महिलाओं को मिलने वाले कुपोषण राशि तथा कोरोना के दौरान मिलने वाली 500–500 रुपये की राशि को भी महिलाओं को दिलाने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्वालियर जिले के कार्यकर्ताओं के प्रयास से कराई, अलिनगर, बस्तरी, मोहना, रामनगर आदि गांवों के लगभग 500 लोगों को सोसायटी से 10 किलो चावल दिलवाया गया।

पलायन से लौटे मजदूरों को राहत सामग्री वितरण

स्त्रोत – सूरज आदिवासी, गुना

जिला गुना – लॉकडाउन का दूसरा चरण पुरा होने से पूर्व मध्यप्रदेश से पलायन पर गये मजदूरों की वापसी शुरु हो गई। इस प्रक्रिया में गुना के भी बहुत से मजदूर वापस आये। लेकिन इस बार मजदूर अपने हाथ में कुछ लेकर नहीं लौटे बल्कि जो कमाया था उसे भी खर्च करके लौटना पड़ा। मजदूरों की उस उम्मीद पर पानी फिर गया कि पलायन से प्राप्त मजदूरी से 4–6 माह का खर्च निकल जायेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोगों के पास खाने को भी अन्न कम पड़ने लगा है। ऐसे

सहायता • लोगों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग रखने की दे रहे समझाइश, ताकि कोरोना की चेन टूट सके

एकता परिषद गुना जरूरतमंदों को बांट रही खाद्य सामग्री

में एकता परिषद के द्वारा कुल 193 परिवारों

(नौनेरा–35, बाघेरी–45 और खुटियारी–20, पराठ–47, बरौना–16 और मुहाल कालोनी–30) को खाद्यान सामग्री वितरित किया गया।

जंगल में बसे छोटे से गांव तक पहुँची एकता परिषद राहत सामग्री

स्त्रोत – रामप्रकाश शर्मा, शिवपुरी

जिला शिवपुरी – कोटरा–कोटरी गांव से लोग पलायन करके दूसरे राज्य अथवा जिले में काम की तलाश में जाते रहे हैं। इस वर्ष (2020) भी गांव से 23 परिवार काम की तालाश में मुरैना, ग्वालियर और कर्नाटक के विभिन्न स्थानों पर गये थे। कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार के द्वारा सारा काम बन्द कर दिया गया जिससे इनके सामने खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। इस बात की जानकारी मजदूरों ने एकता परिषद को दी। संगठन के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये इन सभी परिवारों को राहत सामग्री भेजी गई जिससे इन परिवारों को खाने की असुविधा न हो। कुछ ही दिनों में ये 23 परिवार वापस गांव आ गये।

उक्त 23 परिवारों के अलावा जो लोग गांव में रह गये थे उनको भी लॉकडाउन के कारण मजदूरी नहीं मिली। गांव के 7लोग महिनों तक कर्नाटक में फंसे रहे जिनके बुढ़े माता–पिता गांव

में थे। इन बुढ़े माता–पिता के पास जब 3–4 दिन का राशन बचा था तक संगठन के द्वारा इसकी जानकारी प्रशासन को दिया गया। प्रशासन ने भी सक्रियता से काम करते हुये इन सभी परिवारों को राहत सामग्री के रुप में 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 2 किलो चावल, 1 किलो चीनी, तेल, नमक, जीरा और हल्दी, उपलब्ध कराया ।

एकता परिषद एवं नवरचना संस्था जबलपुर ने किया अनाज किट का वितरण

स्त्रोत – श्री संतोषसिंह, मोहला

जिला जबलपुर – कोरोना वैश्विक महामारी के कारण असहाय निराश्रित विकलांगों व विधवाओं को खास तौर पर चिन्हित किया गया गरीब परिवारों के समक्ष भोजन की समस्या उत्पन्न न हो इसलिये एकता परिषद द्वारा ऊँचेहरा विकासखण्ड के ग्राम पोंडी और पिथौराबाद में अनाज किट वितरण किया गया। प्रत्येक किट में 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल,तेल,हल्दी,नमक और साबुन शामिल था।

एकता परिषद के संस्थापक आदरणीय राजा जी का मानना है कि इस कोरोना संकट में पूरे देश और दुनिया मे वंचितों के सामने जो संकट है उससे वैश्विक स्तर पर सहयोग की आवश्यकता है, संगठन हर संभव सहयोग करने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान, एकता परिषद, जय जगत के अंतर्राष्ट्रीय पदयात्री श्री संतोष सिंह, बायोटेक्नालॉजी के सेवानिवृत्त डायरेक्टर डा. सदाचारी सिंह तोमर एवं पद्मश्री बाबूलाल दाहिया ने उपस्थित ग्रामीणों को कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के प्रति जागरुक भी किया। समाजिक दूरी का विशेष ख्याल रखते हुए अनाज किट का वितरण कार्य श्री संतोष सिंह, डा. सदाचारी सिंह,पद्मश्री बाबूलाल दाहिया,वरिष्ठ समाजसेवी श्री बाल्मीक सिंह के

हाथों सम्पन्न हुआ। आगामी दिनों में पोंडी सहित आसपास के अन्य गांवों के ऐसे 50 लोगों को चिन्हित कर जन सहयोग से खाद्यान्न सामग्री बाटने की योजना है।

जिला दमोह –
एकता परिषद के राज्य समन्वयक सुजात खान ने बताया कि ग्राम किला, कंचनपुरा, चिरईपानी के गरीब जरूरतमंद मजदूरों को जवाबदार अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं समाजसेवियों की उपस्थिति में आटा, चावल, दाल, तेल, साबुन, नमक इत्यादि कच्चे राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। साथ ही वैश्विक बीमारी कोरोना से संबंधित आवश्यक जानकारी एवं बचाव के संबंध में ग्रामीणों को समझाया जाएगा। एकता परिषद द्वारा वितरण संबंधी तैयारी कर ली गई है।

प्रवासी मजदूरों को राशन सामग्री का वितरण

जागरण, हिण्डोरिया

जन संगठन एकता परिषद के तत्वावधान में नवरचना समाज सेवी संस्थान मोहला जबलपुर एवं एकता फाउंडेशन ट्रस्ट भोपाल द्वारा ग्राम कंचनपुरा में 25 प्रवासी, गरीब, जरूरतमंद मजदूरों परिवारों में कच्चे राशन सामग्री के पैकेट बांटे गये। साथ ही लॉक डाउन का पालन करने के अलावा कोरोना महामारी से बचने के उपाय गरीब मजदूरों को समझाये गये ! इस मौके पर बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि एकता परिषद द्वारा गरीबों के हित में वर्षों से किये जा रहे प्रयास अत्यंत सराहनीय एवं प्रेरणादायक रहे है। उन्होंने ने इस गरीब हितैषी पुनीत कार्य के लिए संगठन के संस्थापक एवं जय जगत वैश्विक पदयात्रा के सूत्रधार डॉ. राजगोपाल पीव्ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रनसिंह परमार एवं बुन्देलखण्ड-बघेलखण्ड प्रभारी संतोष सिंह का विशेष आभार व्यक्त किया। थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि लॉक डाउन का सभी को विधिवत पालन करना है। इससे आप स्वयं एवं देश सुरक्षित रहेगा। एकता परिषद राज्य समन्वयक सुजात खान ने कहा कि संगठन द्वारा पूरे देश-प्रदेश में गरीबों, भूमिहीनों, आवासहीनों, प्रवासी मजदूरों, खेतिहर मजदूरों, वंचितों के हितार्थ लगातार भोजन सामग्री वितरण एवं पलायनकर्ता मजदूरों के लिये लगातार सरकारों, शासन प्रशासन से समन्वय के साथ उनकी समस्या निदान के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही कोरोना महामारी के प्रति सचेत करने एवं लॉक डाउन पालन के प्रति व्यापक जन जागरण अभियान कार्य क्षेत्रों में चलाये जा रहे हैं।

इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमेंद्र सिंह, पार्षद तैय्यब अली, पूर्व नपाध्यक्ष रामेश्वर ठेकेदार मुबारक राजा मंजीत राज, जावेद अख्तर, राजू नागर, मुखिया अर्जुन आदिवासी, आशा कार्यकर्ता शमीम बानो, एनएएम कमला बाई, डॉ. सीवान खान सहित अनेक ग्रामीण जन मौजूद रहे।

एकता परिषद और मानव जीवन विकास समिति, बिजोरी, मझगवां के पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा जरुरतमंदो को कराया जा रहा भोजन।

स्रोत – कॉरोना रिस्पोंस समूह

जिला कटनी – कटनी जिले से गुजरने वाले श्रमिकों एंव यात्रियों को भोजन पानी उपलब्ध कराने के लिये मानव जीवन विकास समिति एंव एकता परिषद के पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष श्री निर्भय सिंह जी ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि के समय से ही संस्था द्वारा जरुरतमंदों, गरीबों और मुसाफिरों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होने कहा कि – "रोड से मजदूरों का पैदल चलकर घर पहुॅचने का सिलसिला कब तक रुकेगा, यह अभी ठीक से किसी को पता नही। देश के नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपनी हैसियत के अनुसार लोगों की मदद करें, उनका हौसला बढ़ाते रहें ताकि औरंगाबाद या हैदराबाद जैसी कोई भी घटना न घट सके और सभी लोग अपने घर सुरक्षित पहुॅचें।" मानव जीवन विकास समिति एवं एकता परिषद की ओर से पूड़ी पैकेट बनाकर कटनी उमरिया रोड से निकलने वाले लगभग 50-60 भाई बहनों को खाना खिलाया गया। इसके अलावा डंरींहूंद गांव के आगे टोलप्लाजा पर खाना खिलाने की व्यवस्था की गई। चलने वाले लोग अनूपपुर, बिलासपुर और मुंगेली जिले के थे।

धार जिले में वापिस लौटे भील आदिवासियों के बीच जाकर किया खाद्यान सामग्री वितरण

स्त्रोत्र – कॅरोना रिस्पोंस समूह

जिला धार – गुजरात और सूरत में कार्य करने वाले मजदूर मेडीकल जांच के बाद बहुत बड़ी संख्या में वापिस आ रहे हैं। इन सभी के आगे भोजन और राशन की समस्या है। ऐसी स्थिति में एकता परिषद की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा श्रीमति श्रद्धा कश्यप एवं धार के समन्वयक श्री प्रसन्ना बहक ने जाकर राहत अभियान चलाया जिसमें प्रति परिवार 10 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 लीटर तेल और मसालों आदि के साथ-साथ मास्क वितरित किये गये।

पलायन से लौटे मजदूरों को किया खाद्यान वितरित

जिला झाबुआ –

रामा ब्लॉक के 18 अति गरीब परिवारों को दुर्गा बहन ने एकता परिषद के सहयोग से खाद्यान सामग्री प्रदान की और उनकी सूची तैयार कर महिला बाल विकास विभाग को उपलब्ध कराई जिससे कि उन्हे मदद मिल सके।

पलायन से लौटे मजदूरों को किया खाद्यान्न वितरित

नव भारत समाचार पत्र
दिनांक 12 मई 2020

पारा। कोरोना महामारी के चलते देश के विभिन्न प्रदेशों से वापस अपने घरो पर लौटे मजदुरो के पास खाने का राशन पानी उपलब्ध नही होने पर एकता परिषद ने मजदुरो के घरो पर जाकर खाद्यान्न वितरण किया। कोरोना वायरस के चलते पलायन से अपने घरो पर वापस लौटे मजदुरो के पास खाद्यान्न सामग्री का संकट आ पडा। जिसकों लेकर मजदुरो व उनके परिवार का बुरा हाल था, तब इस बात की खबर एकता परिषद की समन्वायक दुर्गा पंवार कों लगी। दुर्गा ने ग्रामीणो से समस्त जानकारी एकत्रीत कर महात्मा गांधी सेवा आश्रम वर्धा करके मजदुरो की मदद करने की बात कही। आश्रम ने दुर्गा के सहयोग से रामा ब्लाक के 9 गांव थिनपुर, बेहडी, बड़ी हिडी, बावड़ी, धांधलपुरा, बलोल, ढोचका, नवापाड़ा व रातीमाली आदी गांवो के लोगो को जो मजदुरी से वापस अपने घरों पर लौटे थे,

अनाज बैंक से कर रहे जरुरतमंद परिवारों को मदद

जिला रायसेन –

रायसेन जिले के रातापानी अभ्यारण्य, जो कि जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर और मुख्य सड़क से 22 किलोमीटर अंदर तक प्रशासन या समाज सेवी संस्थायें राहत सामग्री नही पहुँचा पा रही हैं, ऐसी स्थिति में एकता परिषद अनाज बैंक से अनाज वितरित कर मदद कर रही है। अभी पलायन से वापिस लौटे 29 परिवारों में अनाज बैंक से 15 क्विंटल अनाज दिया गया है।

2. उत्तरप्रदेश

झांसी जिले के 220 परिवारों तक पहुँची एकता परिषद राहत सामग्री

स्त्रोत – सियाराम सहरिया, झांसी

8 मई 2020 को एकता परिषद द्वारा उत्तरप्रदेश के झांसी जिले में प्रवासी आदिवासी मजदूरों के बीच खाद्य सामग्री का निःशुल्क वितरण किया गया। इस राशन–वितरण अभियान के तहत 8 गांवों, सुकुआ, कोटी, नयाखेड़ा, शेखरपुरा, बड़ेरा, टपरियन, रिछारीया और धमकन के 220 परिवारों के बीच कुल 22 क्विंटल आटा और 220 किलो दाल वितरित किया गया।

ग्राम शिवाजी नगर, लक्ष्मणपुरा, बबीना, नई बस्ती सिमरिया आदि गॉवों में 180 परिवारों के बीच 18 क्विंटल आटा और 1 क्विंटल 80 किलो अरहर दाल का वितरण किया गया।

लॉकडाउन लील गया बुंदेलखंड से पलायन पर गए 375 आदिवासियों की साल भर की रोटी

67 किलोमीटर पैदल, 32 दिन इंतजार , 3 दिन बस यात्रा , दो दिन की जांच के बाद पहुंचे घर।

उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जो एक समय बहादुरी तथा समृद्धि के लिए विख्यात था, जहां के जल प्रबंधन को देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते थे, वही बुंदेलखंड पिछले दो दशकों से सूखा, अकाल , गरीबी और बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। प्रतिवर्ष बुंदेलखंड क्षेत्र से मजदूरी करने के लिए हजारों की संख्या में लोग निकल कर उत्तर भारत की ओर जाते हैं। 2 महीने की मजदूरी करने के बाद 3 या 4 महीने के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था करके लाते हैं लेकिन अब इस मौसमी पलायन की स्थिति भी पूरी तरह से बदल चुकी है।

10 वर्ष पहले जहां बुंदेलखंड के लोग आसपास के जिलों में फसल कटाई के लिए जाते थे वहीं अब दूर जाने लगे हैं क्योंकि इस क्षेत्र में फसल कटाई के लिए बड़ी मशीनों का उपयोग होने लगा है जिससे मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया है ।

राजस्थान के जैसलमेर व जोधपुर जिले, जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे हुए हैं,में बड़े पैमाने पर जीरे की फसल उगाई जाती है। जीरे की फसल को हाथ से ही काटना पड़ता है इसलिए जीरे की कटाई के लिए बुंदेलखंड और ग्वालियर – चम्बल क्षेत्र से बड़ी संख्या में मजदूर राजस्थान जाने लगे हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर से लगभग 1000 किलोमीटर दूर ये लोग जोधपुर और जैसलमेर जिलों में जीरे की कटाई के लिए गए।

झांसी जिले के बबीना तहसील के सुकवा डुकवा गांव के आदिवासियों के पास आज भी आजीविका का कोई संसाधन नहीं है। पूरे गांव के लोग केवल मजदूरी पर निर्भर हैं और मजदूरी यहां आस–पास नहीं मिलती है इसलिए समय–समय पर इस गांव के लोग पूरे परिवार के साथ पलायन करते हैं और मजदूरी से जो पैसा कमा कर लाते हैं उसी से इनका घर चलता है । 12 मार्च को इस गांव के 375 लोग

स्त्रोत – मेवा आदिवासी, झांसी

झांसी से पैसेंजर ट्रेन से जोधपुर के लिये निकले। ये लोग आगरा और जयपुर होते हुये जोधपुर तक की लम्बी यात्रा पैसेंजर ट्रेन से ही पूरी की। रास्ते में ये लोग दो जगह ट्रेन बदलकर 3 दिन में जोधपुर पहुंचे। इनमें वासुदेव आदिवासी, अपनी पत्नी चंदा, मां कलियां तथाा 3 बेटों के साथ मजदूरी करने के लिए गया था। यह पूरा परिवार बहुत उम्मीद लेकर गया था कि 1 महीने की मजदूरी में तीन–चार महीने के लिये राशन/पैसा लेकर आयेंगें जिससे परिवार चलाने की व्यवस्था हो जाएगी।

वासुदेव आदिवासी उसकी पत्नी चंदा, माँ कालिया बाई तथा बच्चों के साथ

17 मार्च से इन लोगों ने जीरे की कटाई का काम शुरू किया। अभी केवल 7 दिन ही काम किया था कि 24 मार्च से पूरे देश में लोक डाउन घोषित हो गया। जैसे ही यह पता लगा कि पूरे देश में रेलगाड़ी, बस आदि सब बंद हो

चुकी है तथा वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है तो मजदूर काफी परेशान हुये। कोई रास्ता न देखकर लॉकडाउन के दौरान सभी लोग प्लास्टिक की सीट की झोपड़ी बनाकर खेत में रहने के लिये मजबूर हो गये। पीने के पानी के लिए खेत के मालिक ने टैंकर की व्यवस्था की थी क्योंकि इस क्षेत्र में पानी का भारी संकट था कुछ मजदूरों ने लॉक डाउन के तुरंत बाद अपना काम छोड़कर घर लौटना शुरू किया लेकिन ये सभी 375 लोग चार–पांच दिन और काम किये। 30 मार्च के बाद इन मजदूरों का काम भी बंद कर दिया गया। इस बीच उन्होने जो कुछ कमाया था उसी में से खरीद–खरीद कर अपने खाने की व्यवस्था की। 1 सप्ताह के बाद पीने का पानी भी समाप्त हो रहा और गांव के लोगों ने भी इन मजदूरों पर गांव छोड़कर वापस जाने का दबाव बनाया। ऐसी परिस्थिति में इन लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें और कहां जाएं।

इसी बीच इन लोगों ने एकता परिषद के साथी जय सिंह भाई से फोन पर संपर्क किया तथा बताया कि किस प्रकार लॉक डाउन में यहां फॅस गए हैं और वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। एकता परिषद के लोगों ने तमाम स्वयंसेवी संगठनों, राजनीतिक प्रतिनिधियों तथा सरकार के अधिकारियों के साथ संपर्क किया और यह प्रयास किया कि किसी प्रकार वहां इनकी भोजन की व्यवस्था हो जाए। काफी प्रयास के बाद दो–तीन दिन के लिए उस पंचायत के सरपंच के द्वारा राशन की व्यवस्था हुई। लेकिन लोगों को लगा कि यहां पड़े रहने से अच्छा है पैदल ही निकल पड़े इसलिए अपने पूरे परिवार के साथ सभी 375 लोग पैदल ही निकल पड़े। लगभग 65 किलोमीटर की दूरी तय करके ये लोग 3 दिन में (27 अप्रैल) को फलोदी गांव पहुंचे। फलोदी गांव में पुलिस ने इनको रोक दिया और आगे नहीं जाने दिया। पुलिस ने इनके रहने की व्यवस्था एक स्कूल में कर दी। अब इनके पास आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, केवल एक ही सहारा था – मोबाइल, जिसके माध्यम से लगातार यह लोग संपर्क कर रहे थे। कुछ समय पश्चात इनके मोबाइल के बैलेंस भी समाप्त होने लगे। उन्होंने एकता परिषद के साथ इस समस्या को साझा किया। एकता परिषद ने इस दल के 9 लोगों के मोबाइल में बैलेंस डलवाया ताकि उनके साथ लगातार संवाद स्थापित होता रहे। जब तक ये लोग फलौदी में रहे तब तक लगातार उनके साथ संवाद होता रहा। उस दौरान सरकार के साथ भी संवाद जारी रहा। 375 लोगों के इस समूह में जो पढ़े–लिखे लड़के थे उनसे एकता परिषद ने फलौदी में इकट्ठे लोगों की एक सूची मंगाई ताकि पता चल सके कि कुल कितनी संख्या में लोग यहां फंसे हुए हैं।

लॉकडाउन के तीसरा चरण में सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्रवासी मजदूरों को घर वापिसी की व्यवस्था की जाएगी। सबसे पहले मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के मजदूरों को लेकर 12 बसें फलोदी से सवाई माधोपुर तक आई लेकिन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के लोग अभी तक इंतजार में बैठे थे। जब एकता परिषद के साथियों ने राजस्थान सरकार से संवाद स्थापित किया तब उत्तर प्रदेश के लोगों को भेजने की तैयारी शुरु हुई और इन 375 लोगों को 12 बसों में फलोदी से आगरा के लिए रवाना किया गया। लम्बी यात्रा के बाद राजस्थान सरकार ने बुंदेलखंड के लोगों को उत्तर प्रदेश की सीमा में छोड़ दिया। यहां भी सभी लोगों को 4 घंटे इंतजार करना पड़ा उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन सभी मजदूरों को झांसी भेजने की व्यवस्था की। इस प्रकार 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद ये सभी लोग झांसी पहुंचे, लेकिन झांसी में भी इन सबको शासकीय स्कूल में छोड़ा गया वहां सब की स्क्रीनिंग हुई। स्क्रीनिंग की इस प्रक्रिया में भी पूरी रात सभी लोगों को स्कूल में ही रुकना पड़ा यद्यपि सरकार ने भोजन के पैकेट की व्यवस्था की थी। इन सभी के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग करने के बाद सुकवा डुकवा गांव में छोड़ा गया।

संतोष अपनी पत्नी और बचचों के साथ, ग्राम– सुकुवा, झांसी

एक–एक कर जब सभी वापस आए मजदूरों से बात की गई तब उन्होंने कहा की जान बची और अब हम कभी इतनी दूर मजदूरी करने नहीं जाएंगे। हम लोगों ने पूरा डेढ़ महीने का समय बहुत मुश्किलों में काटा है।

संतोष, उनकी पत्नी इमरतीबाई और बड़ा बेटा संजय, आदेश के साथ जीरे की कटाई के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि "हमारा तो धैर्य टूट रहा था लेकिन एकता परिषद के लोग फोन कर हमें हिम्मत बंधाते रहे इसलिए आज हम लोग सुरक्षित घर पहुंच गए हैं" ।

3. छत्तीसगढ़

प्रयोग समाज सेवी संस्था और एकता परिषद, छत्तीसगढ़ द्वारा पलायन परिवारों को राशन सामग्री वितरण

स्त्रोत – मंतराम निषाद, तिल्दा

जिला रायपुर, तिल्दा – छत्तीसगढ़ के बाहर गये प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को कोरोना वायरस महामारी के विषम परिस्थिति में काम नही कर पाने के कारण अपने परिवार को आर्थिक सहयोग करने से वंचित रह गये हैं। घर पर रह रहे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रयोग समाज सेवी संस्था और एकता परिषद, छत्तीसगढ़ द्वारा बीते कई दिनों से राशन सामग्री देकर पीड़ित परिवारों को राहत देने की पहल की जा रही है। राशन वितरण के साथ ही लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरुक करने के लिये गरियाबंद जिले के 42 गाँवों में युवा साथियों के द्वारा दीवाल लेखन किया गया है। मास्क लगाने लोगों को दुरी बनाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करने तथा बाहर से आने वाले लोगों को अस्पताल भेजे जाने आदि सबंधी लियमों का पालन कराया गया और जानकारी भी दी गई है। क्षेत्र के 14 गाँव के 36 अति गरीब परिवारों को राशन सामग्री वितरित किया

गया जिसमें चावल,दाल,तेल,आलू,प्याज,नमक आदि शामिल था। लॉकडाउन के बाद इस क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर प्रयोग समाज सेवी संस्था व्यापक कार्य योजना बनाने का सोच रहा है। इस अभियान में क्षेत्र के युवा साथियों को साथ लेकर संचालन करेंगे।

ग्राम पंचायत भूरसुदा व आश्रित गाँव गुजरा में लॉक डाउन के दौरान पलायन में फँसे परिवारो के बच्चों एवम बुजुर्गो व जरूरत मंद 50 परिवारों को खाद्यसामग्री, साबुन, व आवश्यक सामान प्रयोग आश्रम, एकता परिषद, तिल्दा द्वारा वितरित किया गया ।

प्रयोग समाज सेवी संस्था द्वारा पलायन परिवारों को राशन सामग्री दी गई

पायनियर संवाददाता ◀ तिल्दा नेवरा
www.dailypioneer.com

छत्तीसगढ़ के बाहर गये पलायन परिवारो के आक्षितों को कोरोना वायरस महामारी के विषम परिस्थिती में काम नही कर पाने के कारण अपने परिवार को आर्थिक सहयोग करने से वंचित रह गये हैं घर पर रह रहे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक हो रही हैं। ऐसी स्थिति में प्रयोग समाज सेवी संस्था द्वारा बिते दिन सूखा राशन सामग्री देकर पिड़ीत परिवार को राहत देने की पहल किया गया हैं।

यह पहल ग्राम पंचायत भुरुसुदा के संरपच श्रीमति सुशिला राजकुमार साहू द्वारा पलायन परिवार के आश्रितों को मदद करने के लिए आग्रह इस राहत अभियान में भुरुसुदा व गुजरा के पलायन परिवार को सहयोग करने के लिए चिन्हित किया गया था जिसके लिए राशन समाग्री का किट तैयार किया गया तथा आंगन बाड़ी केन्द्र गुजरा तथा पंचायत भवन भुरूसुदा में केन्द्र शासन व राज्य शासन के दिशा निर्देश जिसमें समाजिक दूरिया ,एवंम मास्क पहनना अन्य नियमों का पालन किया गया। इस दौरान कोटवार भूपेन्द्र सिंह चौहान,पंचगण छन्नू यदु,धमेन्द्र ,राधे निषाद, आंगन बाड़ी कार्यकत्ता श्री मति कलिया वर्मा, के साथ साथ गांव के वरिष्ठ नागरिक भी उपस्थित रहे। व प्रयोग समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष सीता राम सोनवानी, तथा कार्यकत्ता रमेश यदु ,द्वारा यह राहत समाग्री का वितरण किया गया।

जिला कोरिया –

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रहने वाले 20 प्रवासी मजदूर, जो जैतहरी पावर प्लांट में काम करने आये थे, पावर प्लांट में काम बंद कर दिये जाने के कारण पैदल ही वापिस सोनभद्र लौट रहे थे। पैदल चलने से वह बहुत ही थके और भूखे थे। एकता परिषद के साथियों ने इन मजदूरों को ग्राम टिकुरी टकीला में रोककर रात्रि भोजन कराया एवं सुबह भोजन करा कर आगे रवाना किया गया ।

प्रवासी मजदूरों के लिये प्रशासन की ओर से काम और संगठन की ओर से मास्क व साबुन

स्त्रोत – श्रद्धा रमानी टिल्दा एवं रघुवीरदास

छत्तीसगढ़ राज्य के 7 जिलों रायपुर, गरियाबन्द, कोंडागान, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा और जशपुर जिलों में मनरेगा योजना के तहत काम शुरू हो गया है और पलायन से लौटने वाले मजदूरों को रोजगार मिल सका है। अभी तालाब गहरीकरण, डबरी निर्माण, नहर निर्माण, बांध निर्माण और कहीं–कहीं भूमि समतलीकरण का काम किया जा रहा है। जो कि सामूहिक रूप से हो रहा है।

कोरोना महामारी को देखते हुए जो भी सरकार द्वारा नियम बनाये गए हैं उन नियमों का पालन करवाने का प्रयास किया जा रहा है। मनरेगा में काम कर रहे मजदूरों के हाथ सफाई के लिए ग्राम पंचायत में विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि वे सब काम करने के बाद अपने घर जाने के पहले साबुन से अपने हाथों को धोकर के ही जायें। मनरेगा के तहत काम प्रारंभ होने के पहिले दिन प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों जैसे पंचायत सचिव, सरपंच और जनपद सी.ई.ओ.के द्वारा प्रशिक्षण कर यह बताया जा रहा है कि काम करते समय कोरोना से बचने संबंधी नियमों का विशेष ध्यान रखें। यानि 1 से 2 मी. की दुरी बनाये रखें और जिस स्थान पर काम शुरु किया गया है वही पर एक सप्ताह तक काम करते रहे। भविष्य में जब प्रवासी मजदूर क्रमशः अपने–अपने राज्यों में वापिस आ जायेगें और उनकी 14 दिनों के क्वारंटाइन की अवधि समाप्त हो जाएगी तब उन मजदूर लोगों का पंजीयन करवाया जाएग और उनको काम में फिर से लगवाने का प्रयास किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा और कोरबा जिले के तीन ब्लॉक– कोरबा, पौड़ीउपरोड़ी और उदयपुर में बड़े पैमाने पर पलायन से लौटे मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया गया है लेकिन काम के दौरान कोरोना से बचने के लिये मजदूर न तो मास्क पहन रहे हैं, न नियमानुसार साबुन से हाथ धोने के नियमों का पालन कर रहे है और न ही दूरी बना कर काम कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना बढ़ने का खतरा बढ़ गया है अतः इस क्षेत्र के संगठन से जुड़े सभी कार्यकर्ता मनरेगा के तहत तालाब निर्माण हो रहे गांवों जैसे डोंगर तराई, महेशपुर, पंडरीपानी, बैरा, चन्द्रौटी, रिखी, प्रेमनगर आदि में जाकर काम करने वाले मजदूरों को मास्क पहनने और हाथ धोने के महत्व को समझाये और कई जगहों पर साबुन और मास्क का वितरण भी किये।

4. ओड़िसा

पलायन से लौटे मजदूरों को एकता परिषद, ओड़िसा ने बॉटी खाद्य सामग्री

स्त्रोत – सरोज,दिलीप,रोशनआरा और मधुसूदन

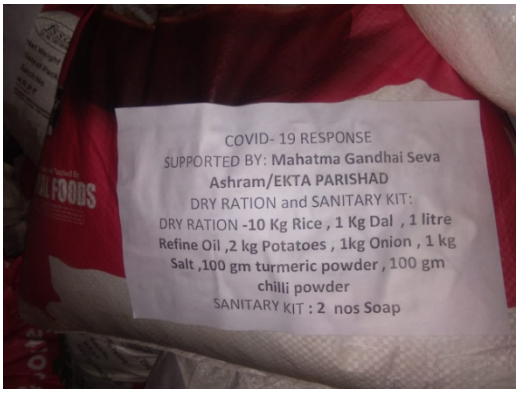

- ओड़िसा के खुर्धा और कालाहांडी जिले के टांगी, भानपुर और एम.रामपुर ब्लॉक के खुंटापल्ली, जुआलीअम्बा, सिलिंगपाड़ा, बेगुनियासाही, डोलागोबिन्दा, नुआसाही, मुडुलीडीहा, बिगनापुट, खरियापाली, पंजीअम्मा आदि लगभग 20 गांवों में राहत सामग्री वितरित की गई।
- ओड़िसा के कार्यक्षेत्र में कुछ गांवों में मनरेगा के तहत काम की शुरुआत की गई है लेकिन जिन गांवों में अभी भी लोगों को काम नहीं मिला है वहां के लिये संगठन की ओर से संबंधित पंचायत और अधिकारी को मजदूरों की सूची सहित आवेदन दिया गया है। इसी क्रम में 6 मई को 20 मजदूरों को काम देने के लिये कालुचुपाटना गांव में संगठन के द्वारा सरपंच को आवेदन दिया गया।
- कॉरोना संक्रमण से बचाव के लिये मास्क व साबुन का वितरण कर हाथ सफाई और सामाजिक दूरी बनाये रखने के बारे में बताया गया।

5. बिहार

पलायन मजदूरों के आश्रितों के बीच राहत अभियान

स्त्रोत – जगत भूषण गया

जिला गया –

एकता परिषद जन संगठन, जीवन जीने के प्राकृतिक संसाधन जल, जंगल और जमीन – ये हो जनता के अधीन के लिए काम करती है। करोना वैश्विक महामारी के कारण तालाबंदी की घोषणा की गयी. परिणाम स्वरुप पलायन करने वाले मजदूरो के सामने विकट स्थिति पैदा हो गई है। एकता परिषद के मुखिया एवं युवा साथियों ने अपने गाँव से देश के विभिन्न राज्यों में पलायन की सूची तैयार किया है।मजदूर परिवार में जिनका राशनकार्ड नहीं है, वैसे चयनित परिवार को 15 दिनों का राशन उपलब्ध कराया गया है और इनका राशन कार्ड बनाने के लिये आवेदन भी किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी भी मौजूद थे. इसमें तालाबंदी के नियमों का पालन किया गया। पलायन से लौटे मजदूरों को मेडीकल जांच एंव 14 दिन के कॉराइंटीन के बाद ही परिवार में रहने दिया गया है। सभी मजदूरों को 2–2 मास्क भी वितरित किये गये हैं।

6. झारखंड

कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड में 36 मजदूर परिवारों के बीच 10 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 लीटर तेल और मसालों का वितरण किया गया।

7. असम

कोरोना संघर्ष में केन्द्रीत होकर काम करने का परिणाम ...

स्त्रोत –डिम्बेश्वरनाथ एवं नयनतारा, असम

जिला धेमाजी – नयनतारा, संगठन में लगभग 1 दशक से सक्रिये कार्यकर्ता के रुप में काम कर रही है। अपने प्रदेश के अलावा देश के अलग–अलग भागों में जाकर अहिंसात्मक आन्दोलनों में भाग लेना और उससे कुछ नया सीखना, इनके स्वभाव में है। एकता परिषद में काम करते हुये इन्होंने संगठन के सभी बड़े–छोटे कार्यक्रमों में पूरी सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ भागीदारी निभाई है जिससे उनको बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है। यही कारण है कि एकता परिषद जैसे अहिंसात्मक जनसंगठन को उत्तरपूर्वी राज्यों को स्थापित करने में जिन लोगों की प्रमुख भूमिका रही है उसमें नयनतारा भी एक हैं। उत्तरपूर्वी राज्यों में से एक असम में कृषि और आवासीय भूमि के मुद्दे उठाने के क्रम में गांव की परिस्थिति को ठीक से समझना और उनके साथ मिलकर समस्या हल करने की कला सीखना, प्रशासन से संवाद करना, मीडिया का उपयोग करना, आस–पास के अन्य संस्थाओं ६ व्यक्तियों को अपने काम के साथ जोड़ना आदि कला सीखने के बाद नयनतारा में आत्मविश्वास बढ़ा।

असम एकता परिषद ने 43 परिवारों को बांटी खाद्य सामग्री

धेमाजी, 6 मई (ए.सं.)। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान असम एकता परिषद की ओर से धेमाजी एवं कामरूप (रूरल) जिले के कई क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। इसी क्रम में भेवेली पंचायत के ग्राम सेवक मोनेश्वर चेतिया और भोमा गांव के युवा नेता रवींद्र दास, बरडोलिनी ग्राम पंचायत की वार्ड सदस्य सुबला चेतिया और उस क्षेत्र के युवा नेताओं ने वितरण व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें मजदूर वर्ग के ऐसे परिवारों का ही चयन किया गया था, जो मजदूरी न मिलने कारण खाद्यान्न के लिए बहुत परेशान थे।

ये सभी अपने गांव व बाहर दूसरे जिले व प्रदेश से बाहर काम करते हैं। कुछ लोग तो लॉकडाउन के कारण बाहर ही फंसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो लॉकडाउन के पहले ही घर आ गए थे। वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया।

इसी प्रकार कामरूप (रूरल) जिले के गुमी, दक्षिण पांतान और सापरतारि ग्राम पंचायत के छयगांव ब्लॉक के आमवाड़ी, पानीखेती, रतनपुर और सापरतारि गांवों में जो लोग बाहर में फंसे हुए हैं या लॉकडाउन से पहले घर वापस आए हुए थे उन 50 परिवारों को चावल, दाल, आलू और नमक वितरित किया गया। इस कार्य में असम एकता परिषद के कार्यकर्ता डिबेश्वर नाथ और निर्मल बारोई, गुमी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष लालमोहन सरकार, सदस्य बिपुल दास उपस्थित थे। इस आशय की जानकारी असम एकता परिषद की कार्यकर्ता नयन तारा ने दी है।

बरडोलिनी पंचायत में खाद्य सामग्री वितरित

धेमाजी, 4 मई (ए.सं.)। असम एकता परिषद की ओर से धेमाजी जिले के गोगामुख तहसील के बरडोलिनी पंचायत में 5 गांवों- बुहाकुरी एनसी, खना कृष्णपुर 1-2 और गोबरथाली 1-2 में लॉकडाउन के कारण प्रभावित अत्यंत गरीब 45 परिवारों को खाद्यान्न सामग्री वितरित की गई। इनमें से 15 परिवारों के खाद्यान्न की व्यवस्था एकता परिषद की कार्यकर्ता नयन तारा के अभिप्रेरित करने पर असम महिला सोसायटी बरडोलिनी उन्नयन खंड, ज्ञान कुश ब्लॉक महासंघ के द्वारा की गई। दोनों संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने चयनित हर परिवार में जाकर खाद्यान्न सामग्री वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर उक्त 5 गांवों के गांवबूढ़ा, सरपंच हरेन सुतिया, एकता परिषद के कार्यकर्ता उज्ज्वल सुतिया और स्थानीय युवा नेता दिगंत सुतिया व पलाश सुतिया सहित स्थानीय महासंघ की कार्यकर्ता रूपाली देवी और संध्याश्री ने वितरण व्यवस्था में सहयोग किया। ध्यातव्य है कि प्रत्येक परिवार में 7 किलो चावल, 2 किलो दाल, 3 किलो आलू, 1 लीटर सरसों का तेल और 1 किलो नमक वितरित किया गया।

कोरोना संक्रमण के इस काल में पलायन पर गये मजदूरों को लेकर संगठन ने जब काम शुरु किया तो नयनतारा ने भी अपने कार्यक्षेत्र के 10 गांवों को केन्द्र में रख कर पलायन पर गये मजदूरों के लिये काम करना शुरु कीं। इस क्रम में नयनतारा को पलायन करने वाले मजदूरों से जुड़ी समस्याओं को नजदीक से देखने और समझने का अवसर मिला और उनसे जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिये नयनतारा ने हर प्रकार से प्रयास कीं। वे बताती हैं कि ''एकता परिषद, असम टीम के द्वारा पिछले 20 दिनों में लगभग 1000 प्रवासी श्रमिकों के बारे में पता लगाकर, उन्हें मदद करने का काम किया गया।''

नयनतारा के कार्यक्षेत्र के 10 गांव, ढेमाजी जिला के गोगामुख तहसील के अन्तर्गत आने वाले 2 पंचायतों, बरडोलिनी और भेवेली में आता है। इन 10 गांवों से लगभग 90 प्रतिशत परिवार मजदूरी के लिये पलायन पर जाते हैं क्योंकि ये सभी 10 गांव बाढ़ प्रभावित है। कोरोना के कारण जब लॉकडाउन की घोषण की गई तो सबसे बड़ी चुनौति यह थी कि पता लगाया जाये कि कितने लोग गांव से बाहर गये हैं और वे कहां है। इस काम में नयनतारा ने स्थानीय वार्ड सदस्य श्री मुक्ता सेतिया, श्रीमती सुबला सेतिया,

गांव के सरपंच श्री हरेन सेतिया तथा युवा साथी श्री रविन्द्र दास से मदद ली। सबकी मदद से पलायन पर गये लोगों की सूची बनाने के बाद उन्हें राहत दिलवाने और घर वापस लाने का प्रयास किया गया। अन्ततः लोग वापस गांव आ गये। गांव आने के बाद लोगों के पास खाने के लिये भी अनाज नहीं था। इसके लिये नयनतारा ने स्थानीय स्तर पर भी प्रयास प्रारंभ कीं और संगठन से भी मदद मांगीं। अब 4 मई से विभिन्न माध्यमों से राहत कार्य चलाया जा रहा है। नसनतारा अपने ही गांव के 83 लोगों को अबतक राहत सामग्री वितरित कर चुकीं हैं। इस कार्य में एकता परिषद का सहयोग तो रहा ही, लेकिन स्थानीय स्तर पर महिला सोसाईटी, बारडोलिनी उनयनखण्ड तथा ज्ञानकुश ब्लॉक महासंघ ने भी मदद की। इन दोनों ही संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने सामान लेने से लेकर, पैकेट बनाने, गांव तक पहुॅचानें को सामग्री वितरण में भी सक्रिये भूमिका निभाई। इस प्रकार संगठन के द्वारा जब एक कार्यकर्ता में नेतृत्व विकास कर दिया जाता है और कार्यकर्ता भी अपने क्षमता विकास के लिये जागरुक रहता है तो काम आसान हो जाता है, चाहे समस्यायें किसी भी प्रकार की हो। इसलिये तो कहा गया है कि – 'केन्द्रीत हो कर काम करना वह कला है जिसके आते ही सफलता निश्चित हो जाता है।'

8. तमिलनाडु

एकता परिषद तमिलनाडु टीम जरुरतमंद परिवारों, बिना राशन कार्ड वाले परिवारों एवं अन्य राज्य के प्रवासी मजदूरों के लिये लगातार सूखा राशन खाद्य सामग्री पहुॅचा रही है।

कोविड-19 बाल सुरक्षा स्वास्थ्य एवं शिक्षा

- कोरोना से बचाव
- सोशल डिस्टेंसिंग
- मास्क का नियमित उपयोग
- स्वच्छता एवं साफ सफाई
- बाल शिक्षा _भय मुक्ति से जिज्ञासा समाधान
- पूरक पोषण आहार
- बाल अधिकारों का संरक्षण

एकता परिषद

एकता परिषद्, संसाधन केन्द्र, पुरानी छावनी थाने के पास, ए.बी. रोड पुरानी छावनी ग्वालियर, सम्पर्क - 9993592425
Contact Persons : Ran Singh Parmar 9993592425, Email: mgsa.india@gmail.com ,
www.mahatmagandhisevaashram.org, www.ektaparishad.org